Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2016

No.11/17//2016-4Lab.— In exercise of powers conferred by Sub-section (2A) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf from time to time, the State Government hereby appoints the Additional Director, Industrial Safety & Health, Haryana, Chandigarh, Joint Director, Industrial Safety & Health, Gurgaon and Deputy Directors, Industrial Safety & Health as Additional Chief Inspector of Factories, Joint Chief Inspector of Factories and Deputy Chief Inspector of Factories respectively for the jurisdiction as per the table to exercise the concurrent powers of the Chief Inspector of Factories for the purpose of approval of factory building plans, registration of factories, issue and renewal of factory licence for the purpose of operation of single window services under one roof established by Haryana Enterprise Promotion Board.

TABLE

Sr. No.	Designation	Appointed as	Area of jurisdiction
1.	Additional Director, Industrial Safety & Health, Chandigarh	Additional Chief Inspector of Factories	Whole of State
2.	Joint Director, Industrial Safety & Health, Gurgaon	Joint Chief Inspector of Factories	District Gurgaon, Rewari, Mahendergarh, Mewat
3.	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Ambala	Deputy Chief Inspector of Factories	District Ambala, Yamunanagar Kurukshetra, Panchkula, Kaithal.
4.	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Panipat	-do-	District Panipat, Karnal, Sonepat, Rohtak, Jhajjar
5.	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Hisar	-do-	District Hisar, Sirsa, Bhiwani, Jind, Fatehabad.
6.	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Faridabad	-do-	District Faridabad, Palwal

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour & Employment Department.

हरियाणा सरकार

श्रम तथा रोजगार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2016

संख्या 11/16/2016–4 श्रम.– पंजाब कारखाना नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनका इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हों, सहित जो सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब कारखाना (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब कारखाना नियम, 1952 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2–क में, ''किसी व्यक्ति की सक्षमता का प्रमाण–पत्र देने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप'' में ''पदीय मोहर'' शब्दों के बाद, '',ई–मेल आइ.डी'' चिह्न तथा शब्द जोड़े जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 में, खण्ड (क) में, ''नाली'' शब्द के बाद ''मलजल'' शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''(3)यदि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत प्ररूप 1–ख में स्थायित्व प्रमाण–पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा।''।

5. उक्त नियम में, नियम 6 में, खण्ड (i) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि कर्मकारों की कोई भी संख्या नियोजित करने वाले सभी कारखानों की दशा में, मुख्य निरीक्षक, जहाँ उसकी संतुष्टि हो जाती है कि कार्य परिस्थितियाँ युक्तियुक्त रूप से अच्छी है, (जहाँ कोई भी वाष्प/धुआँ अथवा खतरनाक गैस निकल रही है तथा जहां वातानुकुलित/शीतलन सुविधाएं उपबन्ध करवाई गई है), इस उप–नियम के उपबन्ध में ऐसे कारखानों को छूट दे सकता है।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप नियम (i) में,–

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा।''

7. उक्त नियमों में, नियम 8 में,–

(i) उप–नियम (1) में, ''एक साल या पाँच साल'' शब्दों के बाद ''या दस साल'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप–नियम (1) में, परन्तुक में, ''पाँच साल'' शब्दों के बाद ''या दस साल'' और ''पाँच गुना'' शब्दों के बाद ''या दस गुना, परिस्थिति अनुसार'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप–नियम (3) में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''**पंजीकरण फीस अनुसूची**

वर्ष के दौरान किसी दिन को नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या

स्थापित अश्व शक्ति की मात्रा (अधिकतम अश्व शक्ति)	20 तक	21 से 40	41 से 150	151 से 250	251 से 500	501 से 1000	1001 से 2000	2001 से 3000	3001 और उससे ऊपर
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
शून्य	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500
10 तक	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000
10 से अधिक किन्तु 50 से अधिक नहीं	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500
50 से अधिक किन्तु 100 से अधिक नहीं	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000
100 से अधिक किन्तु 500 से अधिक नहीं	7500	15000	22500	30000	37500	45000	52500	60000	67500
500 से अधिक किन्तु 1000 से अधिक नहीं	9000	18000	27000	36000	45000	54000	63000	72000	81000
1000 से अधिक किन्तु 2000 से अधिक नहीं	10500	21000	31500	42000	52500	63000	73500	84000	94500
2000 से अधिक	12000	24000	36000	48000	60000	72000	84000	96000	108000''।

8. उक्त नियमों में, नियम 9 में,–

(क) उप नियम (2) में,

(i) अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के संशोधन हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा;'' तथा

(ख) उप–नियम (3) में, ''तीस रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन सौ रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप नियम (2) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

''यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वीकृत समझा जाएगा।''।

10. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप नियम (1) में,–

(i) अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत अनुज्ञप्ति के अन्तरण हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है तो उक्त स्वीकृति प्रदान की गई समझी जाएगी।''।

11. उक्त नियम में, नियम 13 में, –

(i) ''तीस रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन सौ रुपए.'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अन्त में, विद्यमान चिह्न ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' चिह्न प्रस्थिापित किया जाएगा; तथा

(iii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यदि राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत द्वितीय अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पर, इसकी प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया जाता है, तो द्वितीय अनुज्ञप्ति प्रदान की गई समझी जाएगी।''।

12. उक्त नियमों में, नियम 14 में, उप–नियम (1) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''अथवा मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा, चण्डीगढ़ के पक्ष में ई–भुगतान किया जा सकता है।''।

13. उक्त नियमों में, नियम 16 में, ''पंजाब श्रम सेवा (श्रेणी I तथा II) नियम, 1955'' शब्दों कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, ''हरियाणा श्रम विभाग ग्रुप क सेवा नियम, 1996 तथा हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1987'' शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, नियम 16–क में, खण्ड (क) में, द्वितीय पंक्ति में ''फोटोग्राफ'' शब्द के बाद, ''वीडियों रिकार्ड,'' शब्द तथा चिह्न रखा जाएगा।

15. उक्त नियमों में, नियम 17 में,–

(i) उप–नियम (1) में, ''कर सकता है'' शब्दों के स्थान पर, ''करेगा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप–नियम (2) में, खण्ड (क) में,–

(i) अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु असाधारण रूप से योग्य व्यक्तियों की दशा में, जहाँ बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान सम्भव नहीं है, वहां प्रमाणित सर्जन द्वारा यथा अनुशंसित किसी उंगली/हथेली का निशान पर्णिका अथवा प्रतिपर्णिका पर लिया जाएगा।''।

16. उक्त नियमों में, नियम 41 में, खण्ड (ख) के बाद, ''(ख)'' कोष्ठक तथा अक्षर के स्थान पर, ''(ग)'' कोष्ठक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. उक्त नियमों में, नियम 67 में,–

(i) अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–
''इस प्रकार की द्रवचालित सीढ़ियाँ, जहां तक कि ये कर्मकार को इसके प्लेटफार्म से फिसलने/गिरने की सम्भावनाओं को भी रोका जा सके, इस प्रयोजन के लिए भी उपयोग की जा सकती है'';

(ii) अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–
''परन्तु सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका परीक्षण किया गया हो तथा सभी पूर्जों की अच्छी प्रकार से जाँच की गई हो।''।

18. उक्त नियमों में, नियम 72 में, उप–नियम (3) में ''धुलाई स्थान'' शब्दों के बाद, ''तथा शौचघर'' शब्द रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमों में, नियम 74 में, उप–नियम (3) में, परन्तुक में, ''पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1954 (1955 का पंजाब अधिनियम, XIV)'' हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का हरियाणा अधिनियम 22)'' शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

20. उक्त नियमों में, नियम 75 में, उप–नियम (2) में, द्वितीय परन्तुक में, ''पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1954 (1955 का पंजाब अधिनियम XIV)'' शब्दों, चिह्न, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, ''हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का हरियाणा अधिनियम 22)'' शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रस्थिापित किये जाएंगे।

21. उक्त नियमों में, नियम 76 में, उप–धारा (1) में, परन्तुक में, पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1954 ''(1955 का पंजाब अधिनियम XIV)" शब्दों, चिह्न, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, ''हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का हरियाणा अधिनियम 22)'' शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

22. उक्त नियमों में, 95 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(2) यदि कोई कर्मकार अपनी अवकाश पुस्तिका गुम कर देता है, तो प्रबन्धक उसको एक सप्ताह के भीतर अपने रिकार्ड से सम्यक् रूप से पूर्ण करते हुए मुफ्त में दूसरी प्रति उपलब्ध करवाएगा।''।

23. उक्त नियमों में, नियम 103 में,

(i) उप–नियम (1) में, ''विशेष संदेशवाहक या टेलिग्राम'' शब्दों के स्थान पर, ''विशेष संदेशवाहक, ई–मेल या फैक्स'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–नियम (4) में, प्रथम परन्तुक में, ''विशेष संदेशवाहक या टेलिग्राम'' शब्दों के स्थान पर, '' विशेष संदेशवाहक, ई–मेल या फैक्स'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

24. उक्त नियमों में, नियम 105 में, उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(3) अपीलकर्ता को उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत ज्ञापन में कथित करना होगा कि वह किसी पंजीकृत औद्योगिक संघ का सदस्य है। अपीलकर्ता ऐसी औद्योगिक संघ का नाम तथा पता वर्णित करेगा।''।

25. उक्त नियमों में, नियम 108 में, ''पंजीकृत कवर'' शब्दों के स्थान पर ''पंजीकृत कवर या ई–मेल'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा।

26. उक्त नियमों में, नियम 110 में, उप–नियम (1) में, परन्तुक में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े, जाएंगे अर्थात्:–

''उपस्थिति रिकार्ड को डिजिटल रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकता है।''।

शशि गुलाटी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2016

No.11/16/2016-4Lab.- The following draft of rules further to amend the Punjab Factory Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 115 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Labour Department, Chandigarh, from any person in respect of the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Punjab Factory (Haryana Amendment) Rules, 2016.

2. In the Punjab Factories Rules, 1952 (hereinafter called the said rules), in rule 2A, in the "FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF COMPENTENCY TO A PERSON", after the words "Official seal", the words "Email I.D." shall be added in the end of the Form.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (a), after the word "drains", the word "sewerage" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added; namely:-

"(3) If on an application for the acceptance of the stability certificate in form 1B, submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed accepted.".

5. In the said rules, in rule 6, for the second proviso to sub-rule (i), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of all the factories employing any numbers of workers, the Chief Inspector may, where he is satisfied that the conditions of work are reasonably good (where no fumes/smoke or dangerous vapours are produced and where the facilities of air conditioning/cooling is provided) exempt such factories from the provision of this sub-rule.".

6. In the said rules, in rule 7, in sub-rule(1), -

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if on an application for the grant of Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed approved.".

7. In the said rules, in rule 8,-

(i) in sub-rule (1), after the words "one year or five years" the words "or ten years" shall be inserted;

(ii) in the proviso of sub-rule (1), after the words "five years" the words "or ten years" and after the words "five times" the words "or ten times as the case may be" shall be inserted;

(iii) in sub-rule (3), for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

" REGISTRATION FEE

SCHEDULE

Maximum number of workers to be employed on any day during the year.

Quantity of H.P. Installed (Maximum H.P.)	Up to 20	From 21 to 40	From 41 to 150	From 151 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 2000	From 2001 to 3000	From 3001 & above
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Nil	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500
Upto 10	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000
Above 10 but not above 50	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500
Above 50 but not above 100	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000
Above 100 but not above 500	7500	15000	22500	30000	37500	45000	52500	60000	67500
Above 500 but not above 1000	9000	18000	27000	36000	45000	54000	63000	72000	81000
Above 1000 but not above 2000	10500	21000	31500	42000	52500	63000	73500	84000	94500
Above 2000	12000	24000	36000	48000	60000	72000	84000	96000	108000".

8. In the said rules, in rule 9,-

(a) in sub-rule (2),

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if on an application for the amendment of the Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed approved.".

(b) in sub-rule (3), for the word "thirty", the word, "three hundred" shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 10, in sub-rule(2), after the word and sign "licence.", the following words and signs shall be added at the end, namely:-

"If on an application for the renewal of Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said application shall be deemed approved.".

10. In the said rules, in rule 11, in sub-rule(2),-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after sub-rules (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if on an application for the transfer of the Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt, the said permission shall be deemed granted.".

11. In the said rules, in rule 13,-

(i) for the word and sign "thirty.", the words and sign "three hundred:", shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if on an application for the grant of duplicate Licence submitted to the State Government or Chief Inspector, no order is communicated to the applicant within forty-five days from the date of its receipt; the duplicate licence shall be deemed granted.".

12. In the said rules, in rule 14, in sub-rule(1), after the words and sign "Factories Act, 1948" the words and sign "or e-payment can be made in the favour of Chief Inspector of Factories, Haryana, Chandigarh" shall be inserted.

13. In the said rules, in rule 16, for the words and signs "Punjab Labour Service (Class I and II), Rules, 1955", the words and signs "Haryana Labour Department (Group A) Service Rules, 1996 and Haryana Labour Department (Group B) Service Rules, 1987" shall be substituted.

14. In the said rules, in rule 16A, in clause (a), after the word and sign "photograph,", the word and sign "video record," shall be inserted.

15. In the said rules, in rule 17,-

(i) in sub-rule (1), for the word "may", the word "shall" shall be substituted;

(ii) In sub-rule 2, in clause (a),-

(a) for the sign "." exiting at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of differently abled persons where left hand thumb impression is not possible, the impression of any finger/palm as recommended by the Certifying Surgeon shall be taken on the foil and counterfoil.".

16. In the said rules, in the rule 41, after clause (b), for the signs and word "(b)" the signs and word "(c)" shall be substituted.

17. In the said rules, in rule 67,-

(i) after the words "resting on the floor" the words "Hydraulic ladders of such type so as it would prevent the worker from the chances of slip/falling from its platform may also be used for this purpose" shall be inserted;

(ii) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(iii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that hydraulic ladders and all the parts have been thoroughly examined by the Competent Person.".

18. In the said rules, in the rule 72, in sub-rule (3) after the words "washing places", the words "and washrooms" shall be inserted.

19. In the said rules, in the rule 74, in the proviso to sub-rule (3), for the words and signs "Punjab Cooperative Societies Act, 1954 (Punjab Act XIV of 1955)" the words and signs "the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984)" shall be substituted.

20. In the said rules, in rule 75, in 2nd proviso to sub-rule (2), for the words and signs "Punjab Cooperative Societies Act, 1954 (Punjab Act XIV of 1955)", the words and signs "the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984)'' shall be substituted.

21. In the said rules, in the rule 76, in the proviso to sub-rule (1), for the words and signs "Punjab Cooperative Societies Act, 1954 (Punjab Act XIV of 1955)" the words and signs "the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984)" shall be substituted.

22. In the said rules, in the rule 95, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2). If a worker loses his leave book, the manager shall provide him with another copy free of cost duly completed from his record, within one week."

23. In the said rules, rules in 103,-

(i) in sub-rule (1), for the words "special messenger or telegram", the words and sign "special messenger, e-mail or fax" shall be substituted;

(ii) in 1st proviso to sub-rule (4), for the words "special messenger or telegram'', the words and sign "special messenger, e-mail or fax" shall be substituted.

24. In the said rules, in rule 105, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The appellant shall state in the memorandum presented under sub-rule (1), whether he is a member of any Registered Industrial Association. The appellant shall mention the name and address of such Industrial Association."

25. In the said rules, in rule 108, after the words "registered cover", the words and sign "or e-mail" shall be inserted.

26. In the said rules, in the rule 110, in the proviso to sub-rule (1), after the words and sign "need not be maintained.", the words and sign "The attendance record may also be maintained in digital form." shall be added.

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2016

संख्या 8/पीजीटी.II/पं0 अ0 16/1952/धा0 22/2016.– पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

1. ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में, उप–नियम (2ङ)(i) में, खण्ड (क) में,–

(I) क्रम संख्या 3 और 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा; तथा

(II) क्रम संख्या 2 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"3	12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली साधारण बस (कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक)	प्रति माह 125/– रुपये प्रति सीट
4	12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली डीलक्स/अर्ध डीलक्स (कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक)	प्रति माह 175/– रुपये प्रति सीट
5	12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली साधारण वातानुकूलित बस (कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक)	प्रति माह 200/– रुपये प्रति सीट
6	12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली डीलक्स/अर्ध डीलक्स वातानुकूलित बस (कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक)	प्रति माह 300/– रुपये प्रति सीट
7	12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली लग्जरी वातानुकूलित बस (कांट्रैक्ट कैरिज परमिट धारक)	प्रति माह 350/– रुपये प्रति सीट''।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2016

No. 8/PGT-II/P.A. 16/1952/S.22/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Punjab Act 16 of 1952), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Passengers and Goods Taxation Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely: -

1. These rules may be called the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Rules, 2016.

2. In the Punjab Passengers and Goods Taxation Rules, 1952, in rule 9, in sub-rule (2E) (i), in clause (a),-

(I) serial number 3 and 4 and entries thereagainst shall be omitted; and

(II) after serial number 2 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:—

"3	Ordinary bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.125/- per seat per month
4.	Deluxe/ Semi Deluxe bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.175/- per seat per month
5.	Ordinary AC bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.200/- per seat per month
6.	Deluxe/ Semi Deluxe AC bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.300/- per seat per month
7.	Luxury AC bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.350/- per seat per month".

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

(CENTRAL COMMITTEE OF EXAMINATIONS)

DATE-SHEET

Notification

The 16th March, 2016

No. 1/4/2015-1Exam.—The next departmental examinations of various departments of Haryana Government are going to be held in the month of May, 2016 on the dates and time specified below. The examinations will take place in **Lajpat Rai Bhawan**, Sector-15, Chandigarh. For details of the various examinations the intending examinees are referred to the relevant departmental rules:-

Dates and hours	Assistant Commissioners, Extra Assistant Commissioners and the candidates for the post of E.A.Cs.	I.P.S. officers	Civil-Judges and candidates for the posts of Civil-Judges	Tehsildars	Forest Department	Agriculture/ Horticulture Department	Excise and Taxation Department
1	2	3	4	5	6	7	8
02-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	Criminal Law, 1st Paper	---------	---------	Criminal Law, 1st Paper	Forest Law	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	Civil Law	----------	Accounts	Civil Law	Land Revenue	----------	----------
03-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	Criminal Law 2nd Paper	---------	Civil Law	Criminal Law 2nd Paper	Procedure and Accounts	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	Financial Rules	---------	Criminal Law	Financial Rules	Hindi	----------	----------
04-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	Criminal Law, 3rd Paper (including Jails)	----------	Revenue Law, 1st Paper	Criminal Law, 3rd Paper (excluding Jails)	----------	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	Revenue Law, 1st Paper	---------	----------	Revenue Law, 1st Paper	----------	----------	----------
05-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	Local Funds	-------	Revenue Law, 2nd Paper	Local Funds	----------	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	Revenue Law, 2nd Paper	--------	Constitutional Law	Revenue Law, 2nd Paper	----------	----------	----------
06-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	Language (Hindi)	Language (Hindi)	---------	Patwari's Mensuration	----------	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	---------	-------	--------	Urdu	----------	Accounts	----------
10-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	Subject-1 (Law of Crimes)
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	Subject-II (Excise Law)
11-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	Subject-III (Allied Taxes)
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	Subject-IV (Sales Tax Law)
12-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	Subject-V (Book Keeping)
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	Subject-VI (Computer Operation)

Dates and hours	*Animal Husbandry and Dairying Department.	Fisheries Department	Prisons Department	Co-operative Department	Block Development and Panchayats Officers	SDO's Panchayati Raj Deptt. (Enginering Groups)	Wild Life Preservation Department	Elections Department
9	10	11	12	13	14	15	16	17
02-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	Accounts	Accounts	---------	----------	Group-I Paper-A	----------	Account & Departmental Rules	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	*Departmental Rules	*Departmental Rules	---------	----------	----------	I P.W.D. Specifications	----------	----------
03-05-2016 (M) 10.00 a.m.to 1.00 p.m.	----------	---------	----------	----------	Group-I Paper-B	----------	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	----------	---------	----------	Accounts	----------	II Design	----------	----------
04-05-2016 (M) 10.00 a.m. to 1.00 p.m.	----------	----------	Subject-I (Punjab Jails manual without appendices)	----------	Groupt-II (Budget and Accounts)	----------	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	----------	---------	Subject-II (Punjab Jails Manual with appendices) and other matters	----------	----------	III Manual of orders, Accounts and office procedure	----------	Election Laws (For Assistants or Election Kanungos)
05-05-2016 (M) 10.00 a.m.to 1.00 p.m.	----------	-------	Subject-III (Criminal Law)	----------	Group-III (Statutory Acts and Rules)	----------	----------	----------
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	----------	--------	Subject-IV (Financial Rules)	----------	----------	IV Maintenance of T&P Earth Moving and Road making Machinery	----------	--------
06-05-2016 (M) 10.00 a.m.to 1.00 p.m.	----------	----------	Subject-V (Language Hindi)	----------	----------	----------	----------	Administra-tive/ Accounts Rules (For Assistants or Elections Kanungos)
(E) 2.00 p.m. to 5.00 p.m.	----------	----------	--------	----------	----------	Estimating	----------	Election Law (For JSS/ST, Clerks or Moharrirs)

1. * Officers of the Haryana Veterinary Service, Class-I, are not required to appear in this Paper.
2. Those who intend to appear in the examination should immediately apply to their Head of Deptt./Administrative Secretary as the case may be with particulars in the form below by 12th April, 2016. No direct application will be entertained by the Central Committee of Examinations.

   Form → Name of examinee Subject to groups in which the candidate will appear No.s of chance(s) already availed by examinees

   Signature of Examinee
3. The intending examinees who are prevented from appearing in the examination for any reasons should give timely notice to the Secretary, Central Committee of Examinations of their inability to appear.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Co-ordination Department-cum-Secretary,
Central Committee of Examinations, Haryana.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2016

संख्या 20/6/96–4 जे0जे0(1).– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39), की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 20/6/1996–4जे0जे0(1), दिनांक 5 अक्तूबर, 2011 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, माननीय न्यायाधीश श्री अजय कुमार मित्तल, न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को तुरन्त प्रभाव से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते हैं।

पी०के० दास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2016

No. 20/6/96-4JJ(I).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987), and in consultation with the acting Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana and in supersession of Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. 20/6/96-4JJ(1), dated the 5th October, 2011, the Governor of Haryana hereby nominates Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Mittal, Judge of the Punjab and Haryana High Court as Executive Chairman of the Haryana State Legal Services Authority with immediate effect.

P. K. DAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department

54149—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No. 3-HLA of 2016/7.— The Contract Labour (Regulation and Abolition) Haryana Amendment Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 3- HLA of 2016

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HARYANA AMENDMENT

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Haryana Amendment Act, 2016. Short title.

2. In sub-section (4) of section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (hereinafter called the principal Act), - Amendment of section 1of Central Act 37 of 1970.

(i) in clause (a), for the word “twenty”, the word “fifty” shall be substituted; and

(ii) in clause (b), for the word “twenty”, the word “fifty” shall be substituted.

Amendment of section 7 of Central Act 37 of 1970.

3. In sub-section (1) of section 7 of the principal Act,-

(i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, impose such further conditions, as may be deemed necessary, at the time of registration of an establishment or class of establishments for the proper administration of the Act and for prevention of misuse of employment of contract labour.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, is a Central legislation. Presently this Act applies to such establishments employing 20 or more workers as contract labour. At present flexible nature of business requires a larger option of employing workers through outsourcing and this also includes Government establishments, it is, therefore, considered necessary to raise the existing limit to 50 workers for the purpose of application of the Act so far as Haryana State is concerned. This will facilitate flexible deployment of contract labour for medium and small industries.

It has also been experienced that the contractors commonly misuse the provisions of the Act so with a view to curb the exploitation at the hands of the contractor(s), it is proposed to add proviso to sub-section (2) section 7 which may empower the Government to impose further such conditions as may be felt necessary at the time of issuing registration certificate.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister,
Haryana.

_____

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 3–एच.एल.ए.

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970,

हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1970 के केन्द्रीय अधिनियम 37 की धारा 1 का संशोधन।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप–धारा (4) में,–

(i) खण्ड (क) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''पचास'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) खण्ड (ख) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''पचास'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1970 के केन्द्रीय अधिनियम 37 की धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) में,–

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के सुचारू प्रशासन के लिए तथा ठेका श्रम के नियोजन के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी पंजीकरण के समय ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जो आवश्यक समझी जाएं।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 एक केन्द्रीय अधिनियम है। वर्तमान में यह अधिनियम उन संस्थान पर लागू है जहाँ 20 या अधिक ठेका श्रमिकों का नियोजन किया गया हो। वर्तमान के लचीले व्यापार की प्रवृति में व्यापक स्वतंत्रता की आवश्यकता है जिसमें श्रमिकों का बाहय स्त्रोत के माध्यम से नियोजन किया जा सके और इसमें सरकारी संस्थान भी शामिल है तदानुसार यह आवश्यक समझा गया कि हरियाणा राज्य में अधिनियम के निष्पादन के लिये वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 50 श्रमिक कर दिया जाये। इससे मध्यम और लघु उद्योग में ठेका श्रम लगाने के लिये लचीलेपन की सुविधा होगी।

यह भी अनुभव किया गया है कि ठेकादार अधिनियम के प्रभावों का दुरूपयोग करतें है इसलिये ठेकादारों के हाथों शोषण की रोकथाम हेतू कि धारा 7 की उप धारा (2) में यह प्रावधान भी जोड़ना प्रस्तावित है जो सरकार को सशक्त करें कि पंजीकरण पत्र जारी करते समय आगामी शर्तें भी लगाई जा सके।

कैप्टन अभिमन्यु,
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No.4-HLA of 2016/8.— The Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 4- HLA of 2016

THE INDUSTRIAL DISPUTES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.

2. In sub-section (1) of section 25K of the Industrial Disputes Act, 1947,- Amendment of section 25K of Central Act 14 of 1947.

(i) for the word "one hundred", the words "three hundred" shall be substituted;

(ii) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(iii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Chapter to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which less than three hundred workmen, but not less than one hundred as may be specified in the notification, were employed on an average per working day or during the preceding twelve months.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Industrial Disputes Act, 1947, is a Central legislation. As per the existing provisions of section 25 K of the principal Act, the industrial establishments which employ one hundred or more workmen are required to obtain prior permission in respect of lay-off, retrenchment and closure. With a view to facilitate the industry, it is proposed to increase the limit of one hundred workmen to three hundred workmen. However, this limit of three hundred workmen is subject to a rider to the effect that if the State Government is satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, it may apply the provisions to such industrial establishments employing less than three hundred workmen but not less than one hundred, as may be specified by the Government.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 4–एच0एल0ए0

औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25ट की उप–धारा (1) में,– 1947 के केन्द्रीय अधिनियम 14 की धारा 25ट का संशोधन।

(i) "एक सौ" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अन्त में विद्यमान "I" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि औद्योगिक शांति बनाए रखने या इस प्रकार अपेक्षित कर्मकारों के उत्पीड़न के निवारण हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक स्थापना (किसी समय विशेष की स्थापना न होते हुए अथवा जिसमें कार्य केवल अनिरन्तर रूप से निष्पादित किया जाता हो) जिसमें तीन सौ से अधिक किन्तु एक सौ से कम कर्मकार न हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, औसतन प्रति कार्य दिवस पर या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान नियोजित किए गए थे, को इस अध्याय के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक केन्द्रीय अधिनियम है। मुख्य अधिनियम की वर्तमान धारा 25 ट के अनुसार जो औद्योगिक संस्थान 100 से अधिक श्रमिकों का नियोजन करता है और उसे छट्नी, कामबन्दी (ले–ऑफ) या संस्था बन्द करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना वांछित है। उद्योग को सुविधा देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि 100 श्रमिकों की यह सीमा बढ़ाकर 300 कर दी जाये फिर भी यह 300 श्रमिकों यह सीमा पर एक शर्त लगाई जा रही है कि यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट हो कि औद्योगिक शान्ति व श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए यदि वांछित हो तो यह प्रावधान उन औद्योगिक संस्थानों पर भी लागू किया जा सकता है जिनमें 300 से कम श्रमिक हों किन्तु 100 से कम ना हों जैसा कि सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाये।

कैप्टन अभिमन्यु ,
श्रम एवं रोजगार मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.]□□□CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No. 5-HLA of 2016/9.— The Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 5- HLA of 2016

THE FACTORIES (HARYANA AMENDMENT)

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Factories Act, 1948, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Factories (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.

2. In clause (m) of section (2) of the Factories Act, 1948 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 2 of Central Act 63 of 1948.

(i) in sub-clause (i), for the word “ten”, the word “twenty” shall be substituted; and

(ii) in sub-clause (ii), for the word “twenty”, the word “forty” shall be substituted.

3. In clause (iv) of sub-section (3) of section 65 of the principal Act, for the words and sign “seventy five”, the words “one hundred and fifty” shall be substituted. Amendment of section 65 of Central Act 63 of 1948.

Amendment of section 85 of Central Act 63 of 1948.

4. In clause (i) of sub-section (1) of section 85 of the principal Act, for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

Amendment of section 105 of Central Act 63 of 1948.

5. For sub-section (1) of section 105 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by an Inspector with the previous sanction in writing of the Chief Inspector.".

Insertion of section 106B in Central Act 63 of 1948.

6. After section 106A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"106B. Compounding of offences.- The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only, and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence, and where the offence is so compounded,-

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act was enacted in 1948. Its main objective is to ensure the adequate Safety, Health and Welfare of the workers employed in factories.

In the present scenario of Haryana, small scale industries employing less than 20 numbers of workers engaged in manufacturing process with the aid of power (electric power) and 40 numbers of workers without the aid of power, feel uncomfortable to fulfill and comply with the provisions of the Factories Act, 1948. These small scale industries are not able to work efficiently due to various constraints such as labour laws, finance, skilled man power technology etc. In order to release the burden of these small scale industries, the factories having less number of workers may be exempted from the preview of the Factories Act, 1948. It is proposed that the factory having 20 numbers of workers with aid of power and 40 numbers of workers without the aid of power may be exempted from the definition of Factories Act, 1948. For this purpose the amendment in the definition of the factory under sections 2(m)(i) & 2(m)(ii) of the Factories Act, 1948 are required.

The orders for supplying the goods are time bound and the factories are to supply the required goods well before the targeted time and it is the need of the hour to increase the overtime working hours of the factories so that the factories may achieve their targets and fulfill the orders within specified time frame and therefore it is proposed to amend the clause (iv) of sub-section 3 of section 65 of the Factories Act, 1948.

For the cognizance of any offence punishable under the Act, the Occupier or Manager of the factory has to appear before the Court of law for the offences mentioned in the complaint. On pleading guilty, Court imposes penalty on the facts and circumstances of the case. New factories which are not aware of the bylaws of Factories Act, 1948 and Rules framed thereunder got penalized under section 92 of Factories Act, 1948. Under this section the provision of imprisonment for a term which may be extended upto two years or with a fine which may be extended to rupees one lac or with both and if a contravention is continued after conviction the fine may be extended to one thousand rupees for each day on which the contravention of the offence is so continued. The court proceedings are time consuming and expensive. In order to reduce the litigations and to provide the relief to the factories who have committed the offence for the first time may be given opportunity for compounding their offences at Department level instead of going to Court. For these purpose amendments/substitutions under section 105, 106A & 106B of the Factories Act, 1948 are required.

Thus in the view of above and to achieve the object of ease of doing business it has become essential to carry out the above necessary amendments.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 5–एच.एल.ए.

कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016
कारखाना अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम कारखाना (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 2 का संशोधन।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ड) में,–

(i) उप–खण्ड (i) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर, ''बीस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) उप–खण्ड (ii) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''चालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 65 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (3) के खण्ड (iv) में, ''पचहत्तर'' शब्द के स्थान पर, ''एक सौ पचास'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 85 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) में, ''दस'' तथा ''बीस'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''बीस'' तथा ''चालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 105 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 105 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) कोई भी न्यायालय, मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्व स्वीकृति से निरीक्षक द्वारा शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।''।

1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 106ख का रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 106क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''**106ख. अपराधों का प्रशमन**.– निरीक्षक, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, या तो अभियोजन के संस्थित से पूर्व या के बाद, प्रशमन फीस की ऐसी राशि, जैसा वह उचित समझे, की वसूली पर जो अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न हो, प्रशमन कर सकता है तथा जहां अपराध इस प्रकार प्रशमित किया गया है,–

(i) अभियोजन के संस्थित से पूर्व, अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा तथा यदि वह हिरासत में है, तो मुक्त किया जाएगा;

(ii) अभियोजन के संस्थित के बाद, प्रशमन अपराधी की विमुक्ति के बराबर होगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कारखाना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था, इसके मुख्य उद्देश्य कारखानों में नियोजित कर्मकारों को पर्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है।

हरियाणा के वर्तमान दृश्यलेख में, लघु उघोगों में विद्युत की सहायता (इलैक्ट्रिक विद्युत) से विनिर्माण प्रक्रिया में लगाए गए कर्मकारों की संख्या 20 से कम तथा विद्युत की सहायता के बिना कर्मकारों की संख्या 40 से कम का नियोजन कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों को पूरा करने तथा अनुपालन करने में असुविधाजनक है। ये लघु उद्योग विभिन्न प्रतिबन्धों जैसे कि श्रम कानूनों , वित्त, निपुण मानव शक्ति प्रौद्योगिकी इत्यादि के कारण दक्ष रूप से कार्य करने के योग्य नहीं हैं। इन लघु उद्योगों को भारमुक्त करने के उद्देश्य से कर्मकारों की कम संख्या रखने वाले कारखानों को कारखाना अधिनियम, 1948 के पूर्वदर्शन से छूट दी जा सकती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि विद्युत की सहायता से 20 कर्मकारों की संख्या तथा विद्युत की सहायता के बिना 40 कर्मकारों की संख्या रखने वाले कारखाने को कारखाना अधिनियम, 1948 की परिभाषा से छूट प्रदान की जाए। इस प्रयोजन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(ड) (i) तथा 2(ड) (ii) में कारखाने की परिभाषा में संशोधन करना आवश्यक है।

माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश समयबद्ध है तथा लक्षित समय से ठीक पहले कारखानों में अपेक्षित माल की आपूर्ति करना अपेक्षित है तथा कारखानों के अधिक समय कार्य घण्टों में बढ़ोतरी करना समय की आवश्यकता है ताकि कारखाने अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आदेशों को पूरा कर सकें तथा इसलिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा 3 के खण्ड (iv) में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है।

अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संज्ञान के लिए, कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक को शिकायत में वर्णित अपराध के लिए विधि न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ता है। दोषी की वकालत पर न्यायालय मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर शासित अधिरोपित करता है। नए कारखाने जो कारखाना अधिनियम, 1948 की उपविधियों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के जानकार नहीं हैं उन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 के अधीन दण्डित किया जाता है। इस धारा के अधीन कारावास की अवधि का उपबन्ध जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित हो सकता है तथा यदि दोषसिद्धि के बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकता है जिसको अपराध का उल्लंघन इस प्रकार जारी रहता है। न्यायालय कार्यवाही में समय नष्ट होता है तथा यह खर्चीला भी है। वाद को कम करने तथा कारखानों को राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से जिन्होंने प्रथम बार के लिए अपराध किया है को न्यायालय में जाने की बजाय विभागीय स्तर पर उनके अपराधों के प्रशमन के लिए अवसर दिया जा सकता है। इन प्रयोजनों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 105, 106 क तथा 106 ख में संशोधन/प्रतिस्थापन करना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत तथा कारोबार करने की सुगमता के उद्देश्य से इसे प्राप्त करने के लिए उपरोक्त आवश्यक संशोधन करने अनिवार्य हो गए हैं।

कैप्टन अभिमन्यु,
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No.6-HLA of 2016/10.— The Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 6- HLA of 2016

THE PAYMENT OF WAGES (HARYANA AMENDMENT BILL), 2016

A

BILL

further to amend the Payment of Wages Act, 1936, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Payment of Wages (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.

2. Sub-section (6) of section 1 of the Payment of Wages Act, 1936, (hereinafter called the principal Act, shall be omitted). Amendment of section 1of Central Act 4 of 1936.

3. In the proviso to section 6 of the principal Act,- Amendment of section 6 of Central Act 4 of 1936.

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the industrial establishment, the employers of which shall pay to the persons employed therein, the wages either by cheque or by crediting the wages in their bank account.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Payment of Wages Act, 1936, is Central Legislation. In sub-section (6) of section 1 the Central Government is competent authority to fix/revise the wage limit of persons employed in industrial establishments. The existing limit of such wage is Rs. 18,000/- per month. There is a provision to review this wage limit after a period of five years. It has been felt that this wage limit needs to be removed in the present scenario as the manufacturing industry in Haryana has been very progressive and the wage levels are usually high. Therefore, with a view to provide remedy to those who are getting wages at higher rate to enable them to agitate their claim in case of delayed payment of wages or illegal deduction from their wages before the statutory Authority appointed under the Act, this amendment has been proposed.

Further it has been also considered to add a second proviso to section 6 of the principal Act to enable the State Government to specify the industrial establishment, the employers of which shall pay to the persons employed therein, the wages in the particular mode of payment.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 6–एच0एल0ए0

मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम मदजूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, की धारा 1 की उप–धारा (6) (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), का लोप कर दिया जाएगा। 1936 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक में,– 1936 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 6 का संशोधन।

(i) अन्त में विद्यमान "I" के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक स्थापना विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके नियोजन उसमें नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा या उनके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके कर सकेंगे।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वेतन संदाय अधिनियम, 1936 एक केन्द्रीय अधिनियम है। किसी औद्योगिक संस्थान में नियोजन किये हुये किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के अन्तर्गत होने के लिए वेतन की सीमायें निश्चित करना/पुनः निर्धारण करने के लिए धारा 6 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सक्षम है। इस वेतन सीमा पर पांच वर्ष के बाद पुनः विचार करने के लिए प्रावधान है। वर्तमान दृष्टावली में यह महसूस किया गया है कि यह वेतन सीमा हटा दी जानी चाहिए क्योंकि हरियाणा का उत्पादन उद्योग बहुत प्रगतिशील रहा है और उसमें वेतन की दरें सामान्यता ऊंची हैं। इसलिए जो ऊंची दरों से वेतन ले रहे हैं उन्हें देरी से वेतन, गैर कानूनी कटौती के विवादों के समाधान के लिए अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष दावे प्रस्तुत कर सकें इसके लिए यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

इसके आगे यह भी विचारा गया कि मुख्य अधिनियम की धारा 6 में एक दूसरा प्रावधान भी किया जाये जिससे राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई औद्योगिक संस्थानों में अपने द्वारा उसमें नियुक्त किये गये व्यक्तियों को एक निश्चित माध्यम से वेतन देना होगा अर्थात् चैक द्वारा अथवा बैंक खाते में जमा करके संदाय करेगा।

कैप्टन अभिमन्यु,
श्रम एवं रोजगार मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.